उत्तरांचल शासन भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001

आदेश

07 अप्रैल, 2005 ई0

संख्या 76/उत्तरां0—वि0स0/2004(उप)—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तरांचल राज्य से विधान समा के लिए उप निर्वाचन, 2004 में 45—द्वाराहाट विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री प्रमोद कुमार, ग्राम—बैरती, पोस्ट—चित्रेश्वर, जिला—अल्मोड़ा, उत्तरांचल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, जबिक अभ्यर्थी श्री प्रमोद कुमार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है:

अतः, अब, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में श्री प्रमोद कुमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,
एस0 के0 कौरा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi--110001

ORDER

April 07, 2005

No. 76/UCL-LA/2004(Bye)--WHEREAS, the Election Commission is satisfied that Shri Pramod Kumar, Vill.-Bairati, Post-Chitrayshwar, Distt.--Almora, Uttaranchal, a contesting candidate for the Bye Election to the Legislative Assembly, 2004 from 45--Dwarahat Assembly Constituency in the State of Uttaranchal has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made thereunder; and

Whereas, Shri Pramod Kumar has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, Therefore, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said Shri Pramod Kumar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By Order,

S. K. KAURA,

Secretary,

Flection Commission of India

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 28—05—2005, भाग—7 में प्रकाशित। [प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—] पी०एस०यू० (आर०ई०) 12 निर्वाचन/213—25—06—2005—25 (कम्प्यूटर/रीजियो)।